

आरक्षित निर्णय  
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल  
विशेष अपील नं. 2013 का 52  
चंद्र कट्टा इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड .....अपीलकर्ता  
बनाम  
उत्तराखण्ड राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थी  
विशेष अपील नं. 2013 का 249  
उत्तराखण्ड राज्य और अन्य .....अपीलार्थी  
बनाम  
चंद्र कथा इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड .....प्रत्यर्थी

श्री एस0 के0 पोस्ती, एसपीए नं. 52/2013 में अपीलार्थी/रिट याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता। और एस0पी0ए0नं0 [249/2013](#) प्रत्यर्थी/याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

श्री मोहित मौलखेही ने दोनों अपीलों में उत्तराखण्ड राज्य के लिए विद्वान ब्रीफ होल्डर।

श्री वी0के0 कप्रुवान, एसपीए नं. [52/2013](#) में प्रतिवादी नं 03 उत्तराखण्ड वन विकास निगम के लिए विद्वान अधिवक्ता। .

निर्णय सुरक्षित दिनांक 29.11.2018

निर्णय दिनांक 18.12.2018

संदर्भित मामले:

1. (1980) 3 एससीसी 358
2. (2007) 7 वीएसटी 214 (एससी),
3. (2009) 2 एससीसी 326,
4. (1974) 34 एसटीसी 535 (पैट)।
5. (1976) 2 एससीसी 44,
6. (2010) 4 ड.च.स.श्र. 515,
7. (2005) 140 एसटीसी 112 (मैड),
8. (1995) 96 एसटीसी 627
9. (2014) 15 एससीसी 136,
10. (1990) 4 एससीसी 256
11. (2009) 12 एससीसी 735
12. एआईआर 2005 एससी 2891
13. (2005) 4 एससीसी 272
14. (2006) 4 एससीसी 772
15. (2004) 7 एससीसी 377

16. (2005) 7 एससीसी 396
17. (2004) 11 एससीसी 801
18. (2011) 12 एससीसी 499,
19. (1969) 2 एससीआर 253
20. (2004) 11 एससीसी 798
21. (1994) सप.3 एससीसी 606,
  
22. ए. आई. आर. 1992 एससी 152,
23. (2016) 2 एससीसी 362
24. (2016) 15 एससीसी 733
25. (2018) 9 एससीसी 1
26. ए. आई. आर 1961 एस. सी. 65 27.(2002) 5 एससीसी 203 28. 1990 एमएचएलजे 824 29.(1992) 3 एससीसी 750 30. 1979 एस सी 1160 31.ए. आई. आर. 1963 एससी 980 32.ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 548 33ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 563 34ए. आई. आर 1966 एस. सी. 1350 35.ए. आई. आर 1975 एस. सी. 887 36.ए. आई. आर 1971 एस. सी 477
37. (1983) 54 एसटीसी 45 (गुजरात)
38. एआईआर 1981 एससी 446
39. (1973) 2 एससीसी 551
40. एआईआर 1952 एससी 366
41. एआईआर 1964 एससी 1752
42. ए. आई. आर. 1953 एससी 333
43. एयर 1968 पैट. 329
44. (1993) 90 एसटीसी 1 (एससी)
45. (1976) 4 एससीसी 460
46. ए. आई. आर 1996 एस. सी. 1854
47. (2014) 3 एससीसी 732
48. 1935 (37) बॉमलर 866
49. एयर 1997 एससी 2502
50. (1963) पूरक। 2 एस सी आर - 608
51. (1998) 111 एसटीसी 657,
52. (1999) यू पी टी सी- 13,
53. (1998) एसटीसी 111 467,
54. 2008 (230) ई एल टी- 385 (एस सी)

कोरम: माननीय रमेश रंगनाथन, सी0जे0

माननीय आलोक सिंह, जे.

ये दो अपीलें, एक रिट याचिकाकर्ता-विक्रेता द्वारा और दूसरी उत्तराखण्ड राज्य द्वारा, रिट याचिका (एम/एस) नं. 2511/2007 दिनांक 01.11.2012. जबकि विशेष अपील नं. 52/2013 रिट याचिकाकर्ता-विक्रेता, विशेष अपील सं0 249/2013 उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पक्षकारों को, इसके बाद, रिट याचिका में उल्लिखित किया जाएगा।

2. तथ्य, जहां तक आवश्यक है, यह है कि याचिकाकर्ता, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में बिजनौर जिले के नजीबाबाद के कोतवाली रोड पर है, जहां वह अपना व्यवसाय जारी रखती है।

“काठा और कच्छ” के निर्माण और बिक्री में व्यवसाय जो एक प्रकार का टेनिन है और कठ का एक उप-उत्पाद है। काठा के निर्माण के लिए कच्चा माल खैर की लकड़ी है, और याचिकाकर्ता अब तक खैर की लकड़ी वन निगम से खरीद रहा था। याचिकाकर्ता उत्तरप्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (इसके बाद अधिनियम 1948 के रूप में संदर्भित) के तहत एक पंजीकृत विक्रेता भी है। और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (इसके बाद सीएसटी अधिनियम के रूप में संदर्भित)। उन्होंने 1948 अधिनियम की खंड 4-ख के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया और निर्धारण प्राधिकरण ने दिनांक 07.06.1994 के आदेश द्वारा उन्हें मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता कर की रियायती दर पर कच्चा माल खरीदने का हकदार था। यह मान्यता प्रमाणपत्र, दिनांक 09.09.1997 के आदेश द्वारा, कंपनी के जीवनकाल के लिए लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन से पहले, और उत्तराखण्ड राज्य 09.11.2000 को अस्तित्व में आने से पहले, याचिकाकर्ता की विनिर्माण इकाई, और उत्तरप्रदेश से इसकी खरीद का स्रोत। वन निगम, दोनों उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित थे। उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के बाद, जबकि याचिकाकर्ता की इकाई उत्तर प्रदेश राज्य में बनी रही, उत्तराखण्ड राज्य में स्थित निगम से खैर लकड़ी की खरीद की आवश्यकता थी।

3. याचिकाकर्ता का यह मामला है कि इस समस्या को हल करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौता किया गया था, और दोनों राज्यों ने उन व्यक्तियों को कच्चे माल की खरीद के लिए कर की रियायती दर का लाभ देते हुए अधिसूचनाएं जारी कीं, जिनके पास उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन से पहले 1948 अधिनियम की धारा 4-बी के तहत मान्यता प्रमाण पत्र था। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा दिनांक 26.12.2000 को एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें इन निर्माताओं को सीएसटी अधिनियम की धारा 8 (4) के प्रावधानों के अनुसार फॉर्म-सी प्रस्तुत करने पर कर की रियायती दर का लाभ दिया गया था। जबकि यह राजपत्रित अधिसूचना कुछ अन्य शर्तों को भी निर्धारित करती है, हम इस निर्णय में बाद में उनका उल्लेख करेंगे। एक समान अधिसूचना उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 23.11.2000 को जारी किया गया था। उत्तराखण्ड वन विकास निगम (इसके बाद निगम के रूप में संदर्भित) से खैर लकड़ी की खरीद पर, याचिकाकर्ता ने निगम को फॉर्म-सी प्रस्तुत करने का दावा किया, जो, उनका दावा है, इसे प्रतिग्रहण करना करने से इनकार कर दिया, उन्हें कर की रियायती दर का लाभ देने से इनकार कर दिया, और इसके बजाय खैर लकड़ी के खरीद मूल्य पर 15 प्रतिशत कर लगाया।

4. याचिकाकर्ता का यह मामला है कि, चूंकि निगम ने उनके पक्ष में बिल जारी किए और उन्हें उत्तराखण्ड अभिवेदन में उनके चिड़ियापुर डिपो से उत्तर प्रदेश अभिवेदन के नजीबाबाद में याचिकाकर्ता के पते पर खैर लकड़ी के परिवहन के लिए एक पारगमन पास प्रदान किया, यह स्पष्ट था कि माल उत्तराखण्ड अभिवेदन से उत्तर प्रदेश अभिवेदन में चला गया। मूल्य वर्धित कर अधिनियम की शुरुआत के बाद, निगम ने याचिकाकर्ता को चालान जारी किया, जिसमें उनसे 12.5 प्रतिशत व्यापार कर वसूल किया गया जो कर की निर्धारित दर है। वे निगम को फॉर्म-3 बी जमा करते थे, (दिनांक 26.12.2000 की अधिसूचना जारी होने से पहले), कर की रियायती दर का लाभ मांगते हुए, जिससे उन्हें भी इनकार कर दिया गया था। इनके बाद डिवीजन मार्केटिंग मैनेजर निगम दिनांक 09.02.2007 को फार्म सी दाखिल करने पर कर की दर 2.5 प्रतिशत की रियायत बढ़ाये जाने हेतु प्रतिवेदन दिया।

5. याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने कर की नियमित दर पर निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2007-08 तक व्यापार कर का भुगतान किया है उनसे मु0 1,61,26,132/- रुपये कर के रूप में अधिक वसूला गया जो अब उत्तराखण्ड राज्य किसका हकदार है। उन्होंने इस न्यायालय की अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए प्रतिवादी को उनसे 2.5 प्रतिशत से अधिक दर पर व्यापार कर न वसूलने का निर्देश देने का परमादेश दिया जाय। एक परमादेश जो प्रतिवादी को उन्हें मान्यता प्रमाण पत्र का लाभ देने के निर्देश और उत्तराखण्ड राज्य द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26.12.2000 के प्रावधानों का पालन करने के लिए और प्रतिवादीओं को रुपये 1,61,26,132/- रुपये ब्याज के साथ, जो उनसे अवैध रूप से वसूल किया गया था, वापस करने का निर्देश देने वाला एक परमादेश जारी किया जाय।

6. दूसरे प्रतिवादी के अनुसार दाखिल जवाबी अधिसूचना में, वाणिज्यिक कर, हरिद्वार के उपायुक्त द्वारा, यह कहा गया है कि एक विक्रेता केवल अंतर-राज्यीय बिक्री के मामले में फॉर्म-सी प्रस्तुत करने पर रियायती दर पर कर का भुगतान करने का हकदार है। यदि बिक्री एक राज्य के भीतर पूरी हो जाती है, तो फॉर्म-सी जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की बिक्री को अंतर-राज्यीय बिक्री नहीं माना जा सकता है। खैर लकड़ी की बिक्री उत्तराखण्ड राज्य के भीतर समाप्त हो गई थी, और चूंकि याचिकाकर्ता ने इसके अनुसार खुली नीलामी में खरीदा था, नतीजन वह अपने द्वारा खरीदे गए सामान को उत्तराखण्ड राज्य के भीतर या राज्य के बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए स्वतंत्र था। उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद निगम का गठन किया गया था।

7. तीसरे प्रतिवादी-निगम की ओर से दायर जवाबी शपथ पत्र में यह कहा गया है कि निगम भी एक डीलर है। वे वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से कर एकत्र करते हैं, और उनके साथ एकत्रित कर की राशि जमा करते हैं। जैसा कि याचिकाकर्ता, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक कंपनी, ने एक खुली नीलामी में निगम से खैर लकड़ी खरीदी, खैर लकड़ी की बिक्री समाप्त हो गई। उत्तराखंड राज्य के भीतर, और खरीदार इसे कहीं भी स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र था। निगम द्वारा याचिकाकर्ता अधिसूचना किए गए बिलों/चालान में, कर की पूर्ण निर्धारित दर पर व्यापार कर लगाया गया था। निगम को फॉर्म-3 बी जमा करने का सवाल नहीं उठता है क्योंकि यह 01.04.2001 को बनाया गया था। उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद, फॉर्म-3 बी की प्रासंगिकता समाप्त हो गई। याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड राज्य के भीतर निगम द्वारा आयोजित एक खुली नीलामी में खैर लकड़ी खरीदी, यह अंतर-राज्यीय बिक्री का मामला नहीं था, बल्कि उत्तराखंड वन विकास निगम के डिपो में खैर लकड़ी की एकमुश्त बिक्री और खरीद थी क्योंकि बिक्री उत्तराखंड राज्य के भीतर पूरी हो गई थी।

8. याचिकाकर्ता की ओर के अनुसार दायर जवाबी शपथ पत्र में कहा गया है कि उन्होंने खैर लकड़ी की खरीद के समय प्रतिवादी को फॉर्म-सी प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन प्रतिवादी ने फॉर्म-सी को प्रत्युत्तर करने के अनुसार इनकार कर दिया, और उन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा प्रदान की गई कर की रियायती दर का लाभ देने के अनुसार इनकार कर दिया। बिक्री उत्तराखंड राज्य के भीतर पूरी नहीं हुई थी। निगम ने उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर के नजीबाबाद में याचिकाकर्ता के पक्ष में बिक्री बिल व चालान जारी किए हैं। इसने उत्तराखंड राज्य के चिड़ियापुर डिपो के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर के नजीबाबाद के लिए एक पारगमन पास भी जारी किया है। यह याचिकाकर्ता द्वारा की गई खरीद के अनुसार है कि

9. श्री एस0के0 याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता, पोस्टी प्रस्तुत करेंगे कि अधिसूचना का लाभ याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध है क्योंकि बिक्री, मौजूदा मामले में, एक अंतर-राज्यीय बिक्री है। बिक्री के नियम और शर्तों से पता चलता है कि बिक्री एक हथौड़े की बूद पर नहीं हुई थी। बिक्री को पंजीकृत डाक द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचित किया जाना आवश्यक था। इसके तहत सक्षम प्राधिकारी की प्रतिग्रहण करना भी आवश्यक है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि बिक्री नीलामी के लंबे समय बाद हुई थी। यह तथ्य कि उत्तर प्रदेश राज्य में याचिकाकर्ता के नाम पर चालान जारी किए गलती थे, और उत्तराखंड राज्य प्रतिवादी प्रदेश राज्य में माल के परिवहन के लिए उन्हें एक पारगमन पास जारी किया गया था, यह दर्शाता है कि यह एक अंतर-सीखा वकील पर भरोसा करेगा समेकित कॉफी लिमिटेड और एक अन्य बनाम कॉफी बोर्ड, बैंगलोर ख,य उड़ीसा राज्य और एक अन्य बनाम ज़.ठ. साहा एंड संस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ख,य ए एंड जी प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य ख,य और वाणिज्यिक कर आयुक्त बनाम भाग सिंह मिल्खा सिंह ख,।

10. दूसरी ओर उत्तराखंड राज्य की ओर से पेश हुए श्री मोहित मौलेखी ने कहा कि सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खैर लकड़ी की बिक्री हथौड़े के गिरने पर पूरी हो जाती है। उसके बाद निर्धारित अवधि केवल औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए है। बिक्री, मौजूदा मामले में, स्पष्ट रूप से एक अंतर-राज्य बिक्री है। नियमों और शर्तों के लिए बोलीदाताओं को निगम के डिपो में नीलामी में भाग लेने की आवश्यकता थी। खैर लकड़ी की खरीद के बाद, यह याचिकाकर्ता के लिए खुली थी। राज्य के भीतर और बाहर कहीं भी मौजूदा मामले में माल की आवाजाही, बिक्री या खरीद के परिणामस्वरूप नहीं, बल्कि खरीदार की अपनी इच्छा पर की गई थी। नियम और शर्तों में कोई वाचा नहीं है और न ही यह कहा जा सकता है कि माल की आवाजाही बिक्री की घटना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खैर लकड़ी की बिक्री पर एक चालान जारी करने की आवश्यकता है, डीलर का नाम था और उसका पता उसमें परिलक्षित होता है। डिपो से डीलर के परिसर में माल की आवाजाही को सक्षम करने के लिए एक पारगमन पास जारी किया गया था। केवल एक चालान और पारगमन पास जारी करना अंतर-राज्यीय बिक्री के रूप में मानी जाने वाली अंतर-राज्यीय बिक्री को उचित नहीं ठहराएगा और दिनांकित अधिसूचना का लाभ सीखा संक्षिप्त धारक माल की बिक्री अधिनियम, 1930 की खंड 64 पर भरोसा करेगा पर बलभागस हुलासचंद बनाम उड़ीसा राज्य (5) एम एम ट्रेडर्स बनाम स्टेट ऑफ एम पी और अन्य 6 कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड बनामजिला वन अधिकारी, सत्यमंगलम प्रभाग और अन्य 7 और सिमिलीपहाड़ वन विकास निगम लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य अन्य 8।

(क)- प्रासंगिक स्थिति प्रावधान:

11. प्रतिद्वंद्वी विवादों की जांच करने से पहले, सीएसटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, अन्य प्रासंगिक अधिनियमों और सीएसटी अधिनियम की खंड 3 (ए) के दायरे का उल्लेख करना उपयोगी है, जिसमें बिक्री को अंतर-राज्यीय बिक्री के रूप में माने जाने की आवश्यकता होती है यदि माल की बिक्री या खरीद एक राज्य से दूसरे राज्य में इसकी आवाजाही का कारण बनती है। सीएसटी अधिनियम की खंड 8 अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री पर कर की दरों से संबंधित है। उसकी उपखंड (1) के अधीन, प्रत्येक विक्रेता, जिसने अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में, खंड 8 (3) में निर्दिष्ट विवरण के माल को किसी पंजीकृत विक्रेता को बेच दिया था, सी. एस. टी. अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के लिए दायी था, जो उस राज्य की बिक्री कर विधि के अधीन उपयुक्त राज्य के भीतर ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर लागू होने वाली दर पर या उसके कारोबार का विहित प्रतिशत होना था, जो भी कम हो। खंड 8 (4) में कहा गया है कि उप-धारा (1) के उपबंध अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में किसी विक्रय पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि माल बेचने वाला विक्रेता विहित प्राधिकारी को विहित रीति में, उस पंजीकृत व्यापारी द्वारा विधिवत भरी और हस्ताक्षरित एक घोषणा प्रस्तुत नहीं करता है जिसे माल बेचा जाता है जिसमें विहित प्राधिकारी से प्राप्त विहित प्रपत्र में विहित विवरण होते हैं।

12. केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और परिवर्तन) नियम, 1957 के नियम 12 (1) (जिसे इसके पश्चात् "सी. एस. टी. नियम" कहा गया है) में यह विहित किया गया है कि घोषणा और प्रमाण-पत्र, जो खंड 8 (4) में निर्दिष्ट हैं, प्रपत्र सीए और इडीए में होने चाहिए। सीएसटी अधिनियम की खंड 8 (5) में किसी बात के होते के बावजूद राज्य सरकार, विक्रेता द्वारा खंड 8 (4) में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने पर, यदि यह संतुष्ट था कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक था, तो आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन, जो उसमें निर्दिष्ट की जा सकती हैं, निर्देश दे सकती है कि (ए) इस अधिनियम के बशर्ते कोई कर किसी भी व्यापारी द्वारा अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, किसी पंजीकृत व्यापारी को, किसी भी ऐसी वस्तु या माल के वर्ग के व्यापार के किसी भी स्थान से, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, या उस पर कर देय नहीं होगा। इस अधिनियम के अधीन कोई कर देय नहीं होगा या ऐसी बिक्री पर कर की गणना अधिसूचना में उल्लिखित उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसी कम दरों पर की जाएगी। सीएसटी अधिनियम की खंड 8 (5) के खंड (ए) और (बी) के तहत प्रदत्त शक्ति, एक डीलर को कर का भुगतान करने से छूट देने के लिए है, या इस संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने पर खंड 8 (1) में निर्दिष्ट दरों से कम दर पर कर की गणना।

(ख) अधिसूचना दिनांक 26.12.2000 : इसकी सामग्री:

13. अधिसूचना दिनांक 26.12.2000, जिस पर निर्भरता श्री एस0 के0 द्वारा रखी गई है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता पोस्ती इस प्रकार पढ़ते हैं:

६1धविद्वा व्यापार कर/2000 दिनांक:देहरादून: 26 दिसंबर, 2000

(राजपत्र डीटी। 26.12.2000)

जबकि, राज्य सरकार संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है।

अब, इसलिए, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या. 74) की खंड 8 की उप-खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल को यह निर्देश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, उत्तरांचल राज्य में अपना व्यवसाय स्थान रखने वाले किसी भी विक्रेता द्वारा, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, किसी भी ऐसे व्यवसाय के स्थान से, किसी भी कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री, उपभोग्य भंडार, स्पेयर पार्ट्स, सहायक उपकरण, घटक, ईंधन या स्नेहक और पैकिंग सामग्री की बिक्री के संबंध में उक्त खंड की उप-खंड (1) के बशर्ते देय कर। 1948 का गट, जिसकी वैधता 9 नवंबर, 2000 से पहले माल के निर्माण में या उसके द्वारा निर्मित माल की पैकिंग में उपयोग के लिए शुरू होती है, की गणना ऐसी दर पर की जाएगी जो उक्त यू पी के बशर्ते निर्धारित फॉर्म 3 बी के खिलाफ ऐसी बिक्री पर लेवीय होती। एक्ट नं. 1948 का गट, इस शर्त के अधीन है कि माल बेचने वाला विक्रेता फॉर्म (सी) में घोषणा प्रस्तुत करता है, या, जैसा भी मामला हो, फॉर्म (डी) में प्रमाण पत्र उक्त अधिनियम संख्या की खंड 8 की उप-खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार। 1956 का 74.६

(ग) कर की गणना दरें प्रदान करने वाली अधिसूचनाओं का सख्ती से निर्माण किया जाना चाहिए:

14. चूंकि दिनांक 26.12.2000 की अधिसूचना में कुछ डीलरों के लिए कर की रियायती दर का प्रावधान किया गया है, इसलिए इसमें निर्धारित शर्तों का पालन करने पर उक्त अधिसूचना में छूट दी गई है अधिसूचना का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। छूट किसी भी दायित्व, कर या शुल्क के भुगतान से मुक्ति है। यह एक बढ़ती अर्थव्यवस्था में विभिन्न अनुप्रयोगों को मान सकता है जैसे कि नई इकाइयों के लिए कर अवकाश का प्रावधान या विशिष्ट शर्तों के तहत सीमित अवधि के लिए वस्तुओं या व्यक्तियों पर कर की रियायती दर। छूट अधिसूचना के संबंध में पात्रता खंड को सख्त अर्थ दिया जाना है और अधिसूचना की व्याख्या उसकी भाषा के संदर्भ में की जानी है। झारखंड राज्य और अन्य बनाम ला ओपला आर जी, लिमिटेड (9), भारत संघ और अन्य बनाम मेसर्स वुड पेपर्स लिमिटेड और अन्य (10)। छूट का प्रावधान एक अपवाद की तरह है और, कानूनों के निर्माण या व्याख्या के सामान्य सिद्धांत पर, इसका सख्ती से या तो विधायी इरादे या असमान बोझ के आर्थिक औचित्य या राज्य के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से राजकोषीय प्रावधानों के प्रगतिशील दृष्टिकोण के कारण किया जाता है। मेसर्स वुड पेपर्स लिमिटेड. ला ओपला आर जी, लिमिटेड (9)। छूट अधिसूचना को शाब्दिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए, और इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि इसका लाभ उस व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए जो इसके लिए हकदार नहीं है। छूट अधिसूचना के लाभ का दावा करने वाले व्यक्ति को यह दिखाना होगा कि वह पात्रता मानदंड को पूरा करता है। सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक), अमृतसर बनाम मालवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (11),

15. यह एक अधिसूचना के निर्माण का निर्धारित नियम है, जो कर प्रोत्साहन प्रदान करता है, कि, शुरुआत में, यह प्रशासित करने में एक सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए कि क्या एक विक्रेता/निर्माता इसके द्वारा बिल्कुल भी कवर किया गया है। ला ओपला आर जी, लिमिटेड (9)। छूट अधिसूचना का अर्थ उपयोग की गई भाषा के आधार पर लगाया जाना चाहिए। ला ओपला आर जी, लिमिटेड (9), सीसीई, चंडीगढ़ बनाम भल्ला एंटरप्राइजेज (12), टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य और अन्य (13) करतारपुर रोलिंग मिल्स बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली (14), ईगल पलास्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड

अ. केंद्रीय उत्पाद शुल्क पुणे के आयुक्त (15) सरकार। भारत और अन्य बनाम भारतीय तंबाकू संघ (16) मालवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 11, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, त्रिची बनाम रुक्मणी पाकवेल ट्रेडर्स (17),। इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दों के प्रकाश में, और किसी अन्य आधार पर नहीं। खं वंसं त.ळ., लिमिटेड 9य गैमन इंडिया लिमिटेड असीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई ख18, य हंसराज गोरधनदास बनाम २५. दवे, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर और अन्य ख19, यदि अधिसूचना के शब्दों पर, लाभ उपलब्ध नहीं है, तो अधिसूचना के शब्दों को फौलाकर या अधिसूचना में शब्द जोड़कर, कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। खं वंसं त.ळ., लिमिटेड 9य केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़ बनाम महान डेयरी ख20,।

16. यह सिद्धांत कि अस्पष्टता के मामले में एक कराधान अधिनियम का अर्थ निर्धारिती के पक्ष में लगाया जाना चाहिए, एक अपवाद या छूट वाले प्रावधान के निर्माण पर लागू नहीं होता है। उन्हें सख्ती से समझा जाना चाहिए। कर देनदारी से मुक्त करने के लिए अपवाद या छूट प्रावधान का आह्वान करने वाले व्यक्ति को स्पष्ट रूप से यह स्थापित करना चाहिए कि वह उक्त प्रावधान के अंतर्गत आता है। संदेह या अस्पष्टता के मामले में, इसका लाभ राज्य को मिलना चाहिए। यही कारण है कि इस तरह के प्रत्येक अपवाद छूट से समुदाय के अन्य सदस्यों पर कर का बोझ बढ़ जाता है। ला ओपला आर जी, लिमिटेड (9) गैमन इंडिया लिमिटेड (18), मेसर्स. नोवोपान इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद बनाम केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के कलेक्टर, हैदराबाद (21), मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। वाणिज्यिक करों के उपायुक्त और अन्य (22), स्टार इंडस्ट्रीज बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), रायगढ़ (23), मेसर्स वुड पेपर्स लिमिटेड. 10, केवल तभी छूट दी जाएगी जब विषय स्पष्ट रूप से उसमें निहित भाषा के भीतर आता है। खसीमा शुल्क आयुक्त, बैंगलोर बनाम जीई बीई लिमिटेड और एक अन्य (24)।

17. छूट अधिसूचना में या छूट खंड में अस्पष्टता के मामले में, इस तरह की अस्पष्टता का लाभ विषय/निर्धारिती को इस सिद्धांत को लागू करके नहीं दिया जा सकता है कि एक अस्पष्ट और/या अस्पष्ट या संदिग्ध वित्तीय अधिनियम को निर्धारिती के पक्ष में एक निर्माण प्राप्त होना चाहिए। दोनों स्थितियों अलग हैं और, जबकि छूट अधिसूचना पर विचार करते हुए, अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। छूट अधिसूचना की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। प्रयोज्यता साबित करने का भार निर्धारिती पर यह दिखाने का होगा कि उसका मामला छूट खंड या छूट अधिसूचना के मापदंडों के भीतर आता है। जब छूट अधिसूचना में अस्पष्टता है, जो एक सख्त व्याख्या के बशर्ते है, तो इस तरह की अस्पष्टता का लाभ विषय/निर्धारिती द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है, और इसकी व्याख्या राजस्व के पक्ष में की जानी चाहिए। [सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम दिलीप कुमार एंड कंपनी और अन्य] (25).

18. इन सिद्धांतों को ध्यान दें में रखते हुए, आइए अब हम उक्त अधिसूचना में निर्धारित शर्तों पर ध्यान दें दें और उसके बाद, जांच करें कि क्या याचिकाकर्ता ने उन शर्तों को पूरा किया है, क्योंकि यह केवल तभी है जब उसके पास है, तो वह अधिसूचना के लाभ का दावा करने का हकदार होगा। दिनांक 26.12.2000 की अधिसूचना के अनुसार जिन शर्तों को पूरा किया जाना है, वे हैं—

(अ) विक्रेता का उसके द्वारा की गई बिक्री के संबंध में उत्तराखंड राज्य में व्यवसाय का स्थान होना चाहिए, (ब) ऐसी बिक्री अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान व्यापार के ऐसे स्थान से होनी चाहिए, (स) बिक्री (द) किसी कच्चे माल की होनी चाहिए, (बी) प्रसंस्करण सामग्री, (सी) उपभोग्य स्टोर, (डी) स्पेयर पार्ट्स, (ई) सहायक उपकरण, (एफ) घटक, (जी) ईंधन या स्नेहक और (एच) पैकिंग सामग्री, (आई) बिक्री उत्तर प्रदेश राज्य में अपना व्यवसाय स्थान रखने वाले डीलर को होनी चाहिए, (अ) उत्तर प्रदेश में डीलर के पास 1948 अधिनियम की खंड 4-बी के बशर्ते जारी मान्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, (अप) मान्यता प्रमाण पत्र की वैधता 9 नवंबर, 2000 (जब उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया) से पहले शुरू हो गई होनी चाहिए, (ए) माल के निर्माण, और (बी) उसके द्वारा निर्मित माल की पैकिंग में (अपप) इन शर्तों को पूरा करने पर।

या सीएसटी अधिनियम की खंड 8 (4) के अनुसार फॉर्म (डी) में एक प्रमाण पत्र।

19. 1948 अधिनियम की खंड 4-बी कुछ निर्माताओं को विशेष राहत से संबंधित है। यू0पी0 का नियम 25-ठ (1) व्यापार कर नियम, 1948 (जिसे इसके बाद "1948 नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) में यह निर्धारित किया गया है कि जहां मान्यता प्रमाणपत्र रखने वाले किसी व्यापारी ने 1948 अधिनियम की खंड 4-बी (1) (सी) में निर्दिष्ट किसी वस्तु को किसी अधिसूचित वस्तु के निर्माण के उद्देश्य से कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लिए खरीदा है, वह चाहे तो उसमें निर्दिष्ट रियायत का लाभ उठाएगा और विक्रेता को फॉर्म 3-बी में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसे "घोषणा पत्र" कहा जाता है। प्रपत्र 3-ठ क्रय विक्रेता द्वारा विक्रय विक्रेता को दिया जाने वाला एक प्रमाण पत्र है, जो 1948 अधिनियम की खंड 4-बी (1) के तहत कर या कर की रियायती दर से छूट का दावा कर सकता है।

20. मौजूदा मामले में खैर की लकड़ी बेचने वाला विक्रेता वह निगम है जिसका व्यवसाय उत्तराखंड राज्य में है। विक्रेता जिसे इस तरह के सामान बेचे गए हैं, प.म. याचिकाकर्ता का व्यवसाय का स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में है। याचिकाकर्ता-विक्रेता कटहला के निर्माण में भी व्यवसाय करता है, जिसके लिए कच्चा माल खैर लकड़ी है। याचिकाकर्ता के पास 1948 अधिनियम की खंड 4-बी के तहत जारी मान्यता प्रमाण पत्र होने का दावा है, जिसकी वैधता, वे दावा करते हैं, 09.11.2000 से बहुत पहले शुरू हुई थी और उक्त प्रमाण पत्र माल के निर्माण में उपयोग के लिए था प.म। कत्था।

21. विवाद, मौजूदा मामले में, इस सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या याचिकाकर्ता को खैर लकड़ी की बिक्री, निगम के व्यवसाय के स्थान से अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के पाठ्यक्रम में है प.म। उत्तराखंड राज्य में, क्योंकि यह केवल एक अंतर-राज्यीय

बिक्री के मामले में है सीएसटी अधिनियम की खंड 8 (4) याचिकाकर्ता को निगम को फॉर्म-सी में एक घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, और बदले में निगम के लिए व्यापार को उक्त घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कर विभाग। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दिनांक 26.12.2000 की अधिसूचना में निर्धारित शर्तों में से एक यह है कि बिक्री अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होनी चाहिए। चूंकि दिनांक 26.12.2000 की अधिसूचना में कर की रियायती दर का उपबंध है, उसमें विहित शर्तों की पूर्ति पर, और ऐसी अधिसूचना का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए, यह केवल तभी होगा जब माल की बिक्री अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में हो, उक्त अधिसूचना का लाभ याचिकाकर्ता को उपलब्ध होगा।

22. प्रतिवादीओं का दावा है कि चूंकि निगम का गठन उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद किया गया था, इसलिए फॉर्म 3-ट में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का सवाल ही नहीं उठेगा। हमारे लिए इस दलील की जांच करना अनावश्यक है, क्योंकि यह केवल तभी है जब निगम द्वारा याचिकाकर्ता को खैर लकड़ी की बिक्री को अंतर-राज्यीय बिक्री माना जाता है, तो याचिकाकर्ता दिनांक 26.12.2000 की अधिसूचना के लाभ का दावा करने का हकदार होगा, अन्यथा नहीं।

23. याचिकाकर्ता का दावा है कि सामान उत्तराखंड राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य में उनके कारखाने में ले जाया गया। जबकि प्रतिवादी इस बात की अज्ञानता का दावा करते हैं कि क्या माल को वास्तव में उत्तर प्रदेश राज्य में याचिकाकर्ता के कारखाने में ले जाया गया था, वे स्वीकार करते हैं कि याचिकाकर्ता को पारगमन पास जारी किए गए थे ताकि वे उत्तराखंड राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य में माल का परिवहन कर सकें। इसलिए हम, इस मामले के उद्देश्य के लिए, इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि विषय वस्तुएं एक राज्य से दूसरे राज्य में चली गईं, प.म. उत्तराखंड राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य तक। हालांकि, जो सवाल जांच की आवश्यकता बनाता है, वह यह है कि क्या इस तरह की आवाजाही सीएसटी अधिनियम की खंड 3 (ए) के दायरे में आने वाली बिक्री के के अनुसार है?

(घ) सीएसटी अधिनियम की खंड 3 (ए) रूयह स्कोप है:

24. इस प्रश्न की जांच करने से पहले, यह ध्यान दें आवश्यक है कि सीएसटी अधिनियम, संसद को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाया गया था। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-ए के अनुच्छेद 246 और प्रविष्टि 92-क के साथ पठित अनुच्छेद 286 (2) और (3) द्वारा, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में या किसी राज्य के बाहर या भारत में आयात या निर्यात के क्रम में माल की बिक्री या खरीद कब होती है, यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों को तैयार करने के लिए एक अधिनियम था, ताकि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में माल की बिक्री पर करों के उद्ग्रहण, संग्रह और वितरण का प्रावधान किया जा सके, ताकि कुछ वस्तुओं को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व का घोषित किया जा सके और उन प्रतिबंधों और शर्तों को निर्दिष्ट किया जा सके जिनके बर्तन राज्य के कानून, विशेष महत्व की ऐसी वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाते हैं।

25. सी. एस. टी. अधिनियम के अध्याय 2 ने यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों को तैयार किया कि वस्तुओं की बिक्री या खरीद अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या किसी राज्य के बाहर या आयात या निर्यात के दौरान कब हुई थी। सी. एस. टी. अधिनियम के अध्याय 2 में खंड 3, निर्धारित की गई है जब माल की बिक्री या खरीद अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई थी। खंड 3 ने एक कानूनी कल्पना का निर्माण किया, और वस्तुओं की बिक्री या खरीद को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान केवल तभी माना जाना चाहिए जब यह खंड (ए) और (बी) के भीतर आता है। खंड 3 (क) में यह निर्धारित किया गया है कि माल की बिक्री या खरीद अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई मानी जाएगी यदि बिक्री या खरीद एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही का कारण बनती है। खंड 3 (बी) के भीतर बिक्री थी जिसमें माल में संपत्ति माल के हस्तांतरण के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के दौरान पारित की गई थी। खंड 3 (ए) में खंड (बी) में शामिल बिक्री के अलावा अन्य बिक्री शामिल है, जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही बिक्री के अनुबंध के तहत थी, और माल में संपत्ति किसी भी राज्य में पारित की गई थी। खंड 3 (ए) के तहत हुई बिक्री को खंड 3 (बी) के दायरे से बाहर रखा गया था और इसके के स्थान पर अंतर-राज्यीय बिक्री के संबंध में, कर केवल एक बार लगाया जाता था, और यह इंगित करता था कि खंड 3 के दो खंड पारस्परिक रूप से लागू थे। अनन्य खंड 3 (ए) के तहत बिक्री और खंड 3 (बी) के तहत आने वाली बिक्री के बीच विभाजन रेखा यह थी कि, पहले में, आवाजाही अनुबंध के तहत थी, जबकि बाद में, अनुबंध शुरू होने के बाद और समाप्त होने से पहले ही अस्तित्व में आया था। (टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे बनाम एस0आर0) सरकार और अन्य (26), ए एंड जी प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,।

26. अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कराधान के क्षेत्र को राज्य विधानमंडल की क्षमता से बाहर रखा गया था। अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के संबंध में बिक्री या खरीद का स्थान पूरी तरह से महत्वहीन था। सी. एस. टी. अधिनियम की खंड 3 (ए) को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित किया जाना था कि क्या बिक्री या खरीद एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही का कारण है। यदि बिक्री का लेन-देन इस आवश्यकता को पूरा करता है, तो इसे अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री या खरीद माना जाता था और संविधान के अनुच्छेद 269 और 286 के आधार पर, कर लगाने के लिए राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे था। ए0पी0 की स्थिति। और अन्य बनाम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य (27), एस0आर0सरकार 26य 20वीं सेंचुरी फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (28)।

27. सी. एस. टी. अधिनियम की खंड 4 में बताया गया है कि जब माल की बिक्री या खरीद किसी राज्य के बाहर होती है। उसकी उपखंड (1) में यह उपबंध किया गया था कि खंड 3 में अंतर्विष्ट उपबंधों के बशर्ते रहते हुए, जब माल का विक्रय या क्रय उपखंड (2) के अनुसार किसी राज्य के भीतर होने के लिए निर्धारित किया गया था, तो ऐसी विक्रय या क्रय अन्य सभी राज्यों के बाहर हुई मानी जानी चाहिए। खंड 4 (2) में यह निर्धारित किया गया है कि माल की बिक्री या खरीद किसी राज्य के भीतर हुई मानी जानी चाहिए, यदि माल राज्य के भीतर था (ए) विशिष्ट या सुनिश्चित माल के मामले में, बिक्री का अनुबंध किए जाने के समय और (बी) उस समय अप्रमाणित या भविष्य की वस्तुओं के मामले में।

विक्रेता द्वारा या क्रेता द्वारा बिक्री के अनुबंध के लिए उनके विनियोग का, चाहे दूसरे पक्ष की सहमति इस तरह के विनियोग से पहले या बाद में थी। खंड 4 (1) से यह स्पष्ट है कि खंड 4 (2) में डीमिंग प्रावधान सीएसटी अधिनियम की खंड 3 में निहित प्रावधानों के बशर्ते था। यदि माल की बिक्री सीएसटी अधिनियम की खंड 3 (ए) के दायरे में आती है, तो यह एक अंतर-राज्यीय बिक्री होगी, इसके बावजूद कि खंड 4 (2) (ए) के संदर्भ में, निर्धारित माल उस राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर था जहां माल बिक्री का अनुबंध किए जाने के समय था।

28. सी. एस. टी. अधिनियम के तहत, माल की बिक्री पर कर लगाया जाता था, न कि माल की आवाजाही के कारण। माल की आवाजाही केवल यह तय करने के उद्देश्य से सामग्री थी कि क्या बिक्री अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई थी या क्या ऐसी बिक्री विशुद्ध रूप से एक अंतर-राज्य लेन-देन थी। संबंधित पक्षों द्वारा लेन-देन को दिया गया नाम लेन-देन की प्रकृति तय नहीं करता है। सी. एस. टी. अधिनियम के तहत एक लेन-देन को कर योग्य बनाने ठीक होना, लेन-देन सी. एस. टी. अधिनियम की खंड 3 के खंड (ए) या खंड (बी) में प्रदान किए गए किसी भी तरीके से अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली खंड 2 (जी) में परिभाषित "बिक्री" होना चाहिए। (ए एंड जी प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 3)।

29. सी. एस. टी. अधिनियम की खंड 3 (ए) में ऐसी बिक्री शामिल है जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही एक वाचा या बिक्री के अनुबंध की घटना और किसी भी राज्य में पारित माल में संपत्ति का परिणाम थी। (के0बी0 साहा एंड संस इंडस्ट्रीज प्रा. लि.-2 बिक्री कर आयुक्त, यू0 पी0 और अन्य बनाम बख्तावर लाल कैलाश चंद आरेती और अन्य (29), भारत संघ और एक अन्य बनाम के0 जी0 खोसला एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य (30), एस0 आर0 सरकार (26), द सीमेंट मार्केटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम मैसूर राज्य और अन्य (31), स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम मैसूर राज्य (32), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (33), जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य बनाम कैलटेक्स इंडिया लिमिटेड (34), और ऑयल इंडिया लिमिटेड बनाम करों के अधीक्षक और अन्य (35)। यदि बिक्री के अनुबंध में एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के लिए एक शर्त होती है, तो बिक्री निश्चित रूप से एक अंतर-राज्यीय बिक्री होगी। लेकिन यह एक अंतर-राज्यीय बिक्री भी हो सकती है, भले ही बिक्री के अनुबंध में स्वयं एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही का प्रावधान न हो, लेकिन ऐसी आवाजाही बिक्री के अनुबंध में एक वाचा का परिणाम थी या उस अनुबंध की एक घटना थी। (बिहार राज्य और एक अन्य बनाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकमोटिव कंपनी लिमिटेड (36), ऑयल इंडिया लिमिटेड (35) के0 बी0 साहा एंड संस इंडस्ट्रीज प्रा. लि. 2, गुजरात राज्य बनाम बॉम्बे मेटल अलॉयज एंड एमएफजी। को. प्रा. लिमिटेड(37)।

30. सी. एस. टी. अधिनियम की खंड 3 (ए) के प्रयोजनों के लिए और बिक्री को अंतर-राज्यीय बिक्री ठीक होना में माने जाने के लिए, यह मायने नहीं रखता था कि माल में संपत्ति एक राज्य या दूसरे में पारित की गई थी या नहीं। (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) (38) एस0 आर0 सरकार 26, केल्विनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (39), ऑयल इंडिया लिमिटेड 35, बालभागस हुलासचंद 5, और के0 जी0 खोसला एंड कंपनी लिमिटेड. 30, यह भी मायने नहीं रखता था कि एक पूर्ण बिक्री माल की आवाजाही से पहले होती है या उसके बाद होती है। जो महत्वपूर्ण था वह यह था कि माल की आवाजाही और बिक्री अविभाज्य रूप से जुड़ी होनी चाहिए। यदि बिक्री के इकरारनामा के अनुसरण में माल एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया गया था, और बिक्री दूसरे राज्य में पूरी हो गई थी, तो यह एक अंतर-राज्यीय बिक्री थी। के0 बी0 साहा एंड संस इंडस्ट्रीज प्रा. लि. 2, बख्तावर लाल कैलाश चंद आरेती 29,।

31. माल के परिवहन के अवसर ठीक होना, बिक्री के अनुबंध और राज्य के बाहर वास्तविक परिवहन के बीच ऐसा बंधन मौजूद होना चाहिए, कि प्रत्येक लिंक अटूट रूप से उसके तुरंत पहले वाले से जुड़ा हुआ था। जहां परिवहन एक बिक्री का परिणाम था, परिवहन को बिक्री के साथ अटूट रूप से जोड़ा जा रहा था ताकि बांड को आपसी समझ के भंग के बिना अलग नहीं किया जा सके। लेन-देन की प्रकृति से उत्पन्न खरीदार और विक्रेता, बिक्री अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आयोजित की जानी चाहिए। इस तरह की बिक्री का अर्थ न केवल राज्य के क्षेत्र के बाहर माल के परिवहन के अंत के लिए निर्देशित गतिविधियों के दौरान होने वाली बिक्री थी, बल्कि ऐसी गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में या उनसे जुड़ी गतिविधियों के रूप में भी थी। भाग सिंह मिल्खा सिंह 4, त्रावणकोर-कोचीन राज्य और अन्य बनाम बॉम्बे कंपनी लिमिटेड 40, बेन गोर्म नीलगिरी प्लांटेशन कंपनी कुन्नूर (नीलगिरी) और अन्य बनाम बिक्री कर अधिकारी, विशेष सर्कल, एर्नाकुलम और अन्य (41), और त्रावणकोर-कोचीन राज्य और अन्य बनाम षणमुघा विलास काजू फैक्ट्री और अन्य (42), शंकरजी राउत गोपालजी राउत बनाम बिहार राज्य (43)।

32. बिक्री एक अंतर-राज्यीय बिक्री होगी यदि बिक्री के इकरारनामा में कोई शर्त, व्यक्त या निहित था, या माल की आवाजाही आकस्मिक थी और बिक्री या खरीद के आवश्यक परिणाम के रूप में थी। यह कारण और प्रभाव का मामला होना चाहिए, कारण बिक्री और खरीद होना चाहिए, और प्रभाव एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही होना चाहिए। वस्तुओं की बिक्री और आवाजाही एक ही लेन-देन का हिस्सा होना चाहिए। एम0 एम0 व्यापारी 6,। वस्तुओं की आवाजाही और बिक्री अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई होनी चाहिए। बिक्री अनुबंध के अनुसरण में, माल को वास्तव में एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था। एक एकीकृत गतिविधि होनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप माल को आवाजाही में लाया जा सके। एम0एम0 ट्रेडर 6, के0 बी0 साहा एंड संस इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड. 2.



33. यह सवाल कि क्या माल की आवाजाही, एक राज्य से दूसरे राज्य में, बिक्री के अनुबंध में एक वाचा के परिणामस्वरूप थी, या इस तरह के अनुबंध की एक घटना, अनुबंध पर निर्भर करती है। भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड. 32, बिक्री करने के लिए, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, माल को राज्य के बाहर ले जाने का दायित्व होना चाहिए। दायित्व विक्रेता या खरीदार का हो सकता है और यह एक अधिनियम, पक्षों के बीच एक अनुबंध, या उनके बीच आपसी समझ या इकरारनामा के कारण उत्पन्न हो सकता है या यहां तक कि लेन-देन की प्रकृति से भी जो बिक्री को ऐसे परिवहन से जोड़ती है। इस तरह के दायित्व को स्पष्ट रूप से अनुबंध के तहत या निहित रूप से आपसी समझ से लगाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं था कि, सभी मामलों में, लिखित अनुबंध या मौखिक इकरारनामा में इस तरह के दायित्व को दर्शाने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य के टुकड़े होने चाहिए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी इस तरह के दायित्वों का अनुमान लगाया जा सकता था। (भाग सिंह मिलखा सिंह 4, शंकरजी राउत गोपालजी राउत 43)।

34. जहाँ एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही बिक्री/खरीद से अटूट रूप से जुड़ी हुई है, वहाँ खरीद और परिवहन केवल एक लेनदेन का हिस्सा हैं। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, और दूसरे राज्य में माल की खरीद और आवाजाही के बीच कोई विराम नहीं है। यह पर्याप्त है यदि माल की आवाजाही बिक्री में निहित है, और माल की बिक्री और आवाजाही असंबद्ध और असंबद्ध लेनदेन नहीं हैं। सहकारी चीनी (चित्तूर) लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य (44), यदि अंतर-राज्यीय आवाजाही के दौरान माल केवल खरीद के अनुबंध की संतुष्टि में खरीदार तक पहुंचने के लिए जाता है, और ऐसा संबंध अन्यथा अस्पष्ट है, तो बिक्री को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किया गया माना जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बिक्री से माल की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही होती है। इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एक अन्य बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य (45)।

35. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माल की संपत्ति किस राज्य में है। निर्णायक बात यह थी कि क्या बिक्री एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही का कारण थी। यह आवश्यक नहीं था कि बिक्री अंतर-राज्यीय आंदोलन से पहले हुई होगी ठीक होना बिक्री को इस तरह के आंदोलन का कारण माना जा सके। इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड. (45), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड. (27), कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड. 7, महत्वपूर्ण बात यह थी कि माल की आवाजाही और बिक्री अविभाज्य रूप से जुड़े होने चाहिए। यह नहीं था। आवश्यक है कि माल की अंतर-राज्यीय आवाजाही के संबंध में स्पष्ट या निहित प्रावधान को शामिल करते हुए बिक्री का अनुबंध अस्तित्व में होना चाहिए। के0 बी0 साहा एंड संस इंडस्ट्रीज प्रा. लि. 2,।

36. अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में बिक्री करने ठीक होना, माल को राज्य के बाहर ले जाने का दायित्व होना चाहिए। शंकरजी राउत गोपालजी राउत (43), भाग सिंह मिलखा सिंह 4, बेन गोर्म नीलगिरी प्लांटेशन कंपनी कुन्नूर (नीलगिरी) 41,। एक बिक्री, परिभाषा के अनुसार, संपत्ति का हस्तांतरण खंड 3 (ए) के तहत कर योग्य हो गया, यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही बिक्री के अनुबंध की वाचा या एक घटना के तहत थी और माल में संपत्ति दूसरे राज्य में खरीदार को पारित की गई थी। एस0 आर0 सरकार 26,। यदि आवाजाही में व्यवधान था, और अंतर-राज्यीय आवाजाही और अनुबंध के बीच मौजूद अटूट बंधन को तोड़ दिया गया था, तो यह खंड 3 (ए) के तहत अंतर-राज्यीय बिक्री नहीं थी। इन्डियन इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (46),

37. यह आवश्यक नहीं था कि बिक्री के अनुबंध में दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान होना चाहिए। प्रभावी चीनी (चित्तूर) लिमिटेड (44), कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड. 7, यदि बिक्री का अनुबंध, कम से कम निहित रूप से, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के लिए प्रदान करता है तो यह पर्याप्त होगा। कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड. 7, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड. (27), बिक्री के कारण और आंदोलन के प्रभाव में एक संबंध होना चाहिए। एम0 एम0 व्यापारी 6,।

38. यह प्रश्न कि क्या बिक्री एक अंतर-राज्यीय बिक्री थी या नहीं, इस निष्कर्ष पर निर्भर करता है कि क्या बिक्री के अनुबंध के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही हुई थी। यदि माल की आवाजाही, एक राज्य से दूसरे राज्य में, बिक्री के अनुबंध से स्वतंत्र थी, तो यह सीएसटी अधिनियम की खंड 3 (ए) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा। जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसी आवाजाही बिक्री के अनुबंध की वाचा का परिणाम हो सकती है, क्या व्यक्त या निहित, या अनुबंध की एक घटना के रूप में, लेकिन माल की आवाजाही और बिक्री के अनुबंध के बीच एक कड़ी स्थापित की गई होनी चाहिए। सिमिलीपहाड़ वन विकास निगम लिमिटेड 8,।

39. अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान बिक्री में तीन आवश्यक तत्व थे: (अ) माल की अंतर-राज्यीय आवाजाही के संबंध में एक शर्त, व्यक्त या निहित को शामिल करते हुए बिक्री का अनुबंध होना चाहिए, (ब) माल वास्तव में बिक्री के ए के अनुसार अनुबंध के अनुसार एक राज्य के अनुसार दूसरे राज्य में चला गया होना चाहिए, बिक्री आवाजाही का निकटतम कारण है, और (स) माल की ऐसी आवाजाही एक राज्य के अनुसार दूसरे राज्य में होनी चाहिए जहां बिक्री समाप्त हुई हो। इसके बाद, एक आवश्यक परिणाम के रूप में, माल की आवाजाही, जो बिक्री के अनुबंध से स्वतंत्र थी, अंतर-राज्यीय बिक्री के अर्थ में नहीं आएगी। दूसरे शब्दों में, यदि माल की आवाजाही से पहले बिक्री का कोई अनुबंध नहीं था, तो जाहिर है कि आवाजाही को बिक्री के अनुबंध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। इसी तरह, यदि बिक्री का लेन-देन राज्य के भीतर पूरा हो गया था, और उसके बाद माल की आवाजाही हुई थी, तो यह स्पष्ट रूप से बिक्री के अनुबंध से स्वतंत्र होगा, और आवश्यक रूप से केवल खरीदार द्वारा या उसकी ओर से। इसलिए, लेन-देन में अंतर-राज्यीय तत्व नहीं होगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड. (27), कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड. 7, इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड. (45).

40. अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में विक्रय होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता थी।

(अ) विक्रय के लिए एक इकरारनामा था जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के संबंध में व्यक्त या निहित एक शर्त थी, (ब) उक्त अनुबंध के अनुसरण में माल वास्तव में एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया गया था, और (स) अंततः एक निष्कर्ष पर बिक्री उस राज्य में हुई जहां माल भेजा गया था जो उस राज्य से अलग होना चाहिए जहां से माल स्थानांतरित किया गया था। बलभागस हुलासचंद 5, प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों को बदलना होगा और प्रश्न यह है कि क्या, मौजूदा मामले के तथ्यों पर स्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, निगम द्वारा याचिकाकर्ता को खैर लकड़ी की बिक्री को अंतर-राज्यीय बिक्री कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद ही याचिकाकर्ता को दिनांक 26.12.2000 की अधिसूचना में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने के लिए अभिनिर्धारित किया जा सकता है, और, इस प्रकार, उक्त अधिसूचना के संदर्भ में कर की रियायती दर को बढ़ाने का हकदार है।

41. आइए अब हम इस बात की जांच करें कि निगम द्वारा याचिकाकर्ता को खैर लकड़ी की बिक्री एक अंतर-राज्यीय बिक्री थी या नहीं। मौजूदा मामले में, सार्वजनिक नीलामी में प्रतिभागियों, याचिकाकर्ता सहित, निगम के मंडल बिक्री प्रबंधक द्वारा सूचित किया गया था, दिनांक 13.12.2000 के पत्र के माध्यम से, 11 बजे उपस्थित होने के लिए :00 पूर्वाह्न 30.12.2000 को जब देहरादून बिक्री प्रभाग में रायवाला डिपो अ, ब और स में पड़ी 93.0867 घन मीटर खैर लकड़ी की कुल मात्रा के लिए नीलामी आयोजित की जाएगी। जिन बोलीदाताओं को उक्त पत्र संबोधित किया गया था, उनमें से कई उत्तर प्रदेश राज्य में व्यवसाय कर रहे थे, जबकि कुछ अन्य उत्तराखंड राज्य के भीतर व्यवसाय कर रहे थे। याचिकाकर्ता का नाम सीरियल नं. 2, उन व्यक्तियों की सूची में जिन्हें यह संचार भेजा गया था, और उनका पता उसमें कोटवाली रोड, नजीबाबाद के रूप में दिखाया गया था, जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। याचिकाकर्ता को दिनांक 23.01.2001 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि उन्होंने 30.12.2000 को आयोजित नीलामी में कुछ लॉट के लिए खैर लकड़ी खरीदी थी, अनुमोदन तिथि 23.01.2001 थी, उन्हें बैंक ड्राफ्ट जमा करना चाहिए, नकद छूट की अंतिम तिथि 01.02.2001 थी, विलंब शुल्क के बिना, बिक्री मूल्य जमा करने की अंतिम तिथि 15.02.2001 थी, विलंब शुल्क बिक्री मूल्य जमा करने की अंतिम तिथि 22.02.2001 थी, प्लॉट किराए के बिना, लकड़ी उठाने की अंतिम तिथि 08.03.2001 थी, प्लॉट किराए के साथ, लकड़ी उठाने की अंतिम तिथि 23.03.2001 थी, उन्हें बैंक में जमा करना चाहिए। इसके बाद, याचिकाकर्ता को चालान जारी किए गए जिसमें उनका पता कोटवाली रोड, नजीबाबाद, बिजनौर के रूप में दर्शाया गया था। याचिकाकर्ता के वाहन को पारगमन पास भी जारी किए गए थे, और जिस स्थान पर वन उपज का परिवहन किया जाना था, उसे नजीबाबाद (जो उत्तर प्रदेश राज्य में है) के रूप में दिखाया गया था।

#### V- नीलामी की महत्वपूर्ण शर्तें और शर्तें

42. यह निर्धारण ठीक होना कि क्या निगम द्वारा याचिकाकर्ता को खैर लकड़ी की बिक्री एक अंतर-राज्यीय बिक्री है या एक अंतर-राज्यीय बिक्री है, निगम द्वारा निर्धारित बिक्री के प्रासंगिक नियमों और शर्तों का उल्लेख करना आवश्यक है, जो निगम द्वारा खैर लकड़ी की बिक्री और याचिकाकर्ता द्वारा इसकी खरीद में समाप्त हुआ। वे हैं:-

#### नीलामी के महत्वपूर्ण नियम और शर्तें -

1. सभी इच्छुक खरीदार को गेट मनी के रूप में 5,000/- (केवल पांच हजार रुपये) जमा करने होंगे। केवल वे व्यक्ति/खरीदार जो गेट मनी जमा करेंगे, अपने नाम पर बोली जमा समर्थ इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

2. हालांकि बिक्री सूची में लॉट की सामग्री की सही संख्या और माप का उल्लेख करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती गई है, फिर भी खरीदारों से अनुरोध किया जाता है कि वे नीलामी से पहले उन सामग्रियों का निरीक्षण करें जहां वे पड़े हुए हैं और यदि नाग माप लॉट (जालौनी को छोड़कर) में कोई संदेह है, तो उच्चतम बोली राशि का 1 प्रतिशत या रु 200/- है। यदि भिन्नता 2 प्रतिशत से अधिक आती है, तो ऐसे लॉट की नीलामी रद्द कर दी जाएगी और ऐसे लॉट (ओं) के संबंध में खरीदार द्वारा जमा की गई पूरी राशि वापस कर दी जाएगी, लेकिन यदि भिन्नता 2 प्रतिशत से कम आती है, तो बिक्री को मान्य माना जाएगा और सुरक्षा राशि वापस नहीं की जाएगी।

3. खरीदारों से अनुरोध है कि वे लकड़ी के ग्रेड के अनुसार अपनी बोली की पेशकश करें। लॉट बेचे जाने के बाद लकड़ी/लॉट के ग्रेड के बारे में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. लॉट की नीलामी को आम तौर पर उच्चतम बोली के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा, लेकिन वन निगम उच्चतम या किसी भी बोली को प्रतिग्रहण करना करने के लिए बाध्य नहीं होगा। निगम बिना कोई कारण बताए बोलियों को प्रतिग्रहण करना या अप्रतिग्रहण करना करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उच्चतम खरीदार, जिसकी बोली निगम द्वारा स्वीकार की जाती है, नीलामी मूल्य का 10 प्रतिशत सुरक्षा धन के रूप में जमा करेगा। सुरक्षा राशि प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 के पक्ष में नकद या डिमांड ड्राफ्ट में जमा की जाएगी। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय वन निगम। हालांकि, डिमांड ड्राफ्ट के लिए खरीदार से बैंक संग्रह शुल्क की मांग नहीं की जाएगी। इन खर्चों का वहन वन निगम द्वारा किया जाएगा। सुरक्षा राशि जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप लॉट के लिए स्वीकृत बोलियों को रद्द कर दिया जाएगा और गेट मनी को जब्त कर लिया जाएगा।

5. एक बार जब सक्षम प्राधिकरण बोली को मंजूरी दे देता है, तो सफल खरीदार को पंजीकृत डाक द्वारा से भेजे जाने वाले अनुमोदन पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा। सफल खरीदार को सूचना पत्र की प्राप्ति के 24 दिनों के भीतर अनुमोदन पत्र में उल्लिखित देय राशि जमा करनी होगी (पत्र के प्रेषण की तारीख को छोड़कर लेकिन सामान उठाने से पहले)। यदि सूचना पत्र खरीदार को हाथ से दिया जाता है, तो उसे सूचना पत्र की प्राप्ति के बाद 21 दिनों के भीतर सूचना पत्र में उल्लिखित देय राशि जमा करनी होगी (पत्र भेजने की तारीख को छोड़कर लेकिन सामान उठाने से पहले)। यह राशि प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में डिपो कार्यालय में जमा की जाएगी। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय वन निगम। यदि डिमांड ड्राफ्ट में उल्लिखित तिथि से 3 दिनों के बाद कार्यालय में डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होता है, तो भी इसे उसमें उल्लिखित तिथि पर प्राप्त माना जाएगा। बिक्री मूल्य की शेष राशि नकद या बैंक भुगतान पर्ची द्वारा प्राप्त नहीं की जाएगी।

6. एक बार बोली स्वीकृत हो जाने के बाद, खरीदार लकड़ी/वन उपज के परिवहन के समय या उससे पहले नियमों के अनुसार लागू आयकर, व्यापार कर, मंडी शुल्क और पारगमन शुल्क की समेकित राशि के साथ बोली मूल्य जमा करेगा। भविष्य में अन्य केंद्रीय, राज्य और स्थानीय कर या संशोधित कर, यदि कोई हों, जो लगाए जा सकते हैं, सफल खरीदार द्वारा देय होंगे।

6(ए). पक्ष या खरीदार द्वारा व्यापार कर छूट के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, मंजूरी (निकास) उस स्थान पर जाने की अनुमति दी जाएगी जहाँ खरीदार का व्यवसाय पंजीकृत है।

7. लॉट की नीलामी बिक्री के सभी मामलों में, मंजूरी/अनुमोदन की अधिकतम अवधि 40 दिन (नीलामी की तारीख को छोड़कर) होगी। यदि निर्धारित 40 दिनों के भीतर मंजूरी की घोषणा नहीं की जाती है और खरीदार को पंजीकृत डाक द्वारा अनुमोदन पत्र नहीं भेजा जाता है, तो खरीदार लॉट खरीदने से इनकार कर सकता है और ऐसी स्थिति में, इस तरह के लॉट की सुरक्षा राशि खरीदार को वापस की जा सकती है।

8. यदि खरीदार बिल के प्रेषण की तिथि के बाद 10 दिनों के भीतर (प्रेषण की तिथि को छोड़कर) (पहाड़ी क्षेत्रों में शंकुधारी प्रजातियों के लिए 15 दिन) और हैंड डिलीवरी के मामले में, बिल की प्राप्ति की तारीख के बाद 7 दिनों के भीतर संपूर्ण बिक्री मूल्य जमा करता है, तो मैदानी क्षेत्रों में लॉट के मूल्य के 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

9. यदि सफल खरीदार बिल के प्रेषण की तारीख से 24 दिनों के भीतर देय शेष राशि जमा करने में विफल रहता है (प्रेषण की तारीख को छोड़कर) और बिल की हैंड डिलीवरी के मामले में 21 दिनों के भीतर, तो अगले 7 दिनों के लिए 0.25 प्रतिशत प्रति दिन की दर से विलंब शुल्क लगाया जाएगा। यदि खरीदार विलंब शुल्क के साथ 7 दिनों के बाद भी देय राशि जमा करने में विफल रहता है, तो खरीदार द्वारा की गई सुरक्षा के रूप में पूरी जमा राशि बिना किसी सूचना के अधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जाएगी और लॉट की नीलामी रद्द कर दी जाएगी।

10. लकड़ी (आंशिक रूप से या पूरी तरह से) उठाने की अनुमति खरीदार को वैधानिक करें और शुल्कों के साथ शेष भुगतान की प्राप्ति पर ही दी जाएगी।

11. भुगतान के संदर्भ में, डिपो अधिकारी/डिपो लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सील की गई रसीदें ही मान्य होंगी।

12. खरीदार बिल के प्रेषण की तारीख से 45 दिनों के भीतर (यदि बिल हाथ से दिया गया है तो 42 दिन) खरीदे गए लकड़ी को सकारात्मक रूप से उठाएगा। हालांकि, यदि खरीदार किसी भी कारण से पूरी मात्रा को उठाने में विफल रहता है, तो शेष सामान को उठाने की अनुमति भूखंड किराए पर दी जाएगी (भूखंड किराए की दर होगी प्रति दिन आधार पर डिपो में रखी गई शेष मात्रा का 0.25 प्रतिशत) और सामान को 15 दिनों तक डिपो में रखने की अनुमति दी जा सकती है। यदि खरीदार ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस लकड़ी को उठाने में विफल रहता है, तो मंजूरी (निकासी) द्वारा अनुमति दी जा सकती है। अगले 7 दिनों के लिए संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक और अगले 15 दिनों के लिए संबंधित महाप्रबंधक द्वारा उपर्युक्त विस्तारित अवधि के लिए भूखंड किराए की दर भूखंड की शेष मात्रा के मूल्य का 0.50 प्रतिशत होगी।

A- उस लॉट के लिए क्रेता द्वारा जमा की गई कुल राशि वन निगम के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।

B- वन उपज की पूरी मात्रा वन निगम की संपत्ति बन जाएगी और वन निगम बिना कोई सूचना दिए नीलामी या अन्य तरीकों से संपत्ति का निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगा।

/ क्रेता और क्रेता को दी गई जानकारी किसी भी तरह के मुआवजे या नुकसान का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

13. खरीदार को सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही डिपो से लकड़ी उठाने की अनुमति होगी।

14. प्रत्येक लॉट की प्रत्येक वस्तु का मापन वस्तु पर मुद्रित किया जाना चाहिए। सभी लॉट मात्रा के आधार पर बचे जाएंगे न कि वजन के आधार पर।

15. इन नियमों और शर्तों के निष्पादन से उत्पन्न होने वाले विवादों को संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक, यू0 पी0 के मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा। वन निगम जिसका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।”



के विशिष्ट होने और सुपुर्दगी की स्थिति में होने के कारण, सामान में संपत्ति हथौड़े के गिरने पर संबंधित प्रावधान के कारण पास हो जाती है

संपत्ति.खसमेकित कॉफी लिमिटेड. 1, वस्तुओं की बिक्री अधिनियम की खंड 64 (2) नीलामी बिक्री में संपत्ति के पारित होने के प्रश्न से संबंधित नहीं है। यदि चल-सम्पत्ति संपत्तियों की नीलामी बिक्री बिना शर्त है, विशिष्ट निर्धारित वस्तुओं के संबंध में है, और माल को डिलीवरी के लिए तैयार स्थिति में रखने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है, तो माल में संपत्ति बोली की स्वीकृति पर खरीदार को दे दी जाएगी, लेकिन यह खंड 64 (2) के कारण नहीं होगी, बल्कि खंड 20 के कारण होगी।खसमेकित कॉफी लिमिटेड. 1,

47. माल विक्रय अधिनियम, 1930 की खंड 20 एक सुपुर्दगी योग्य स्थिति में विशिष्ट वस्तुओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत, जब किसी सुपुर्दगी योग्य स्थिति में विशिष्ट माल की बिक्री के लिए कोई बिना शर्त अनुबंध होता है, तो अनुबंध किए जाने पर माल में संपत्ति खरीदार के पास चली जाती है, और यदि मूल्य के भुगतान का समय, या माल की डिलीवरी का समय, स्थगित कर दिया जाता है तो यह मायने नहीं रखता है।

48. आम तौर पर नीलामी बिक्री में हथौड़े के गिरने पर बिक्री अनुबंध पूरा हो जाता है, और उस समय तक बोलीदाता अपनी बोली वापस ले सकता है, लेकिन यदि नीलामी बिक्री विशिष्ट और सुनिश्चित वस्तुओं के संबंध में बिना शर्त बिक्री होती है, तो वस्तु बिक्री अधिनियम की खंड 20 के संचालन के कारण हथौड़े के गिरने पर संपत्ति का स्वामित्व एक साथ पारित हो जाता है। समेकित कॉफी लिमिटेड. 1,

49. माल की बिक्री अधिनियम की खंड 19 (3) में यह निर्धारित किया गया है कि खंड 20 से 24 (मौजूदा मामले में, खंड 20) में निहित नियम उस समय पक्षों के इरादे का पता लगाने के लिए नियम हैं, जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो। यह जांचने का अभ्यास कि क्या अनुबंध की शर्तों में या पक्षों के आचरण में या मामले की परिस्थितियों में कुछ भी है, जो एक विपरीत इरादे को इंगित करता है, प्रारंभिक शब्दों को प्रभावी बनाने के लिए किया जाना चाहिए, अर्थात् जब तक कि खंड में कोई अलग इरादा प्रकट न हो। 19 (3)। पक्षों का इरादा निर्णायक कारक है कि माल में संपत्ति कब खरीदार को जाती है। यदि अनुबंध मौन है, तो मामले के आचरण और परिस्थितियों से इरादा एकत्र किया जाना चाहिए। (कृषि उपज बाजार समिति बनाम बायोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य) 47, हो किम सींग बनाम मोंग बा चिट (48) कृषि बाजार समिति बनाम शालीमार केमिकल वर्क्स लिमिटेड (49)।

50. नीलामीकर्ता उन नियमों और शर्तों को निर्धारित कर सकता है जिनके आधार पर संपत्ति नीलामी द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध है। किसी भी बोली की स्वीकृति, साथ ही उस पर बेचे गए माल में संपत्ति का पारित होना, उन नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा। (समेकित कॉफी लिमिटेड. 1, एक नीलामी बिक्री में, जैसे ही हथौड़ा गिरता है, सामान में शीर्षक, आम तौर पर, खरीदार को पारित करता है अगर सामान विशिष्ट सामान हैं यानी i-e- ऐसी वस्तुएँ जिनकी पूर्ण मात्रा में नीलामी की जाती है। ए0 वी0 थॉमस एंड कंपनी लिमिटेड अ. कृषि आयकर के उपायुक्त (50) समेकित कॉफी लिमिटेड. 1, यह माल के विशिष्ट होने और सुपुर्दगी योग्य स्थिति में होने के कारण है कि माल बिक्री अधिनियम की खंड 20 के तहत, ऐसे माल में संपत्ति अनुबंध के पूरा होने पर खरीदार को ऐसी बिक्री पर हथौड़ा गिरने पर पास हो जाती है। ए0 वी0 थॉमस एंड कंपनी लिमिटेड. 50, समेकित कॉफी लिमिटेड. 1,

51. मौजूदा मामले में, विषय वस्तुएं निर्धारित वस्तुएं हैं और सुपुर्दगी योग्य स्थिति में हैं। अनुबंध तब अस्तित्व में आया जब सक्षम प्राधिकारी ने बोली को मंजूरी दी, और याचिकाकर्ता को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया। बिक्री का अनुबंध अस्तित्व में आने पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन पर, माल का मालिकाना हक याचिकाकर्ता को दे दिया गया, भले ही भुगतान का समय निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करने पर, उस तारीख तक स्थगित कर दिया गया था जिस पर वस्तु को उठाया गया था। सीएसटी अधिनियम की खंड 4 (2) (ए) को ध्यान में रखते हुए, निगम द्वारा खैर लकड़ी की बिक्री उत्तराखंड राज्य के भीतर हुई मानी जानी चाहिए जैसा कि कहा गया है माल, जो विशिष्ट और निर्धारित माल थे, बिक्री का अनुबंध किए जाने के समय उत्तराखंड राज्य के भीतर थे। निगम और याचिकाकर्ता के बीच विषय अनुबंध खैर लकड़ी की बिक्री के लिए है, और बिक्री के नियमों और शर्तों से पता चलता है कि बिक्री हुई थी, और माल में संपत्ति याचिकाकर्ता को उत्तराखंड राज्य के भीतर, बोली पर उक्त राज्य के भीतर स्थित सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही है।

52. नीलामी के नियम और शर्तें याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी गई खैर लकड़ी को राज्य के बाहर ले जाने के लिए बाध्य नहीं करती थीं। यह उन लोगों के लिए खुला था, जिन्हें खैर की लकड़ी बेची जाती थी, उन्हें उत्तराखंड राज्य के भीतर या बाहर बेचने के लिए, या उत्तराखंड राज्य के भीतर या राज्य के बाहर अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए इसका उपयोग करने के लिए खुला था। निगम द्वारा याचिकाकर्ता को खैर लकड़ी की बिक्री और राज्य के बाहर इसके परिवहन के बीच कोई संबंध नहीं है। नियम और शर्तें निगम को उत्तराखंड राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश राज्य में परिवहन के लिए माल बेचने के लिए बाध्य नहीं करती थीं। याचिकाकर्ता द्वारा खैर लकड़ी का परिवहन, निगम के डिपो से उत्तर प्रदेश में उनकी विनिर्माण इकाई तक, उनकी इच्छा पर है, न कि बिक्री के अनुबंध के तहत।

53. उत्तराखंड राज्य के अंदर और बाहर स्थित विक्रेताओं द्वारा किए जा रहे प्रस्तावों पर, और निगम से खैर लकड़ी की खरीद के लिए बोलियां जमा करने में अपनी रुचि व्यक्त करने पर, निगम द्वारा उनके संबंधित पतों पर पत्र भेजे गए, जिनमें से कुछ उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर (उत्तराखंड राज्य के बाहर) थे। इसी तरह, खैर लकड़ी की बिक्री पर, सबसे अधिक बोली लगाने वाले पर चालान लगाए गए थे, और उसका पता उस स्थान के रूप में दिखाया गया था जहाँ वह व्यवसाय कर रहा था। यह तथ्य कि उत्तर प्रदेश राज्य में उनके पते पर पत्रों को संबोधित किया गया था, और चालान उठाए गए थे, याचिकाकर्ता अपने आप में और बिना

किसी और चीज के, एक अंतर-राज्यीय बिक्री को अंतर-राज्यीय बिक्री नहीं बना जाएगा। जैसा कि उल्लेख किया गया है इसके अतिरिक्त, बिक्री को एक अंतर-राज्यीय बिक्री माना जाएगा, जो सीएसटी अधिनियम की खंड 3 (ए) के दायरे में आती है, केवल तभी जब बिक्री के अनुबंध और एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के बीच एक अटूट संबंध हो। पत्रों को संबोधित किया जा रहा है और चालान उठाए जा रहे हैं, जैसा कि मौजूदा मामले में किया गया था, बिक्री के अनुबंध और उत्तराखंड राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य में माल की आवाजाही के बीच एक अटूट संबंध का खुलासा नहीं करता है।

54. मौजूदा मामले में, डीलरों की सुविधा के लिए पारगमन पास जारी किए गए थे, और केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता के वाहन को एक पारगमन पास जारी किया गया था, जिससे खैर लकड़ी को उत्तराखंड राज्य के भीतर से, उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर ले जाया जा सके, अंतर-राज्यीय बिक्री के रूप में अंतर-राज्यीय बिक्री नहीं होगी। एम0 एम0 व्यापारी 6.

55. बिक्री के अनुबंध और उत्तराखंड राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य में माल (खैर लकड़ी) की आवाजाही के बीच कोई अभिन्न संबंध नहीं है। माल की बिक्री (i-e- खैर लकड़ी), मौजूदा मामले में, इसलिए सीएसटी अधिनियम की खंड 3 (ए) के दायरे में आने वाली अंतर-राज्यीय बिक्री नहीं कहा जा सकता है। अपील के अधीन आदेश, जिस हद तक विद्वत एकल न्यायाधीश ने इसे सी. एस. टी. अधिनियम की खंड 3 (ए) के दायरे में आने वाली अंतर-राज्यीय बिक्री के रूप में अभिनिर्धारित किया है, उसे तदनुसार अलग रद्दना चाहिए। विशेष अपील नं. 2013 का 249, उत्तराखंड राज्य द्वारा पसंद किया गया है और अपील के तहत आदेश, सी. एस. टी. अधिनियम की खंड 3 (ए) के दायरे में आने वाली विषय बिक्री को अंतर-राज्यीय बिक्री मानता है, को रद्द दिया गया है।

#### VII- अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत:कर के अवशिष्ट की वापसी के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर इसका आवेदन:

56. श्री एस0 के0 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता पोस्ती प्रस्तुत करेंगे कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को धनवापसी का लाभ नहीं देने में गलती थी, गलत तरीके से अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत को लागू किया थाय उक्त सिद्धांत का याचिकाकर्ता के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। मौजूदा मामले यह केवल तभी है जब माल किसी अन्य व्यापारी को बेचा गया था, और कर उन्हें दिया गया था, तो उक्त सिद्धांत लागू होगा, मौजूदा मामले में, उत्तराखंड राज्य से खरीदी गई खैर लकड़ी का उपयोग कट्टे के निर्माण के लिए किया गया था, और इसे किसी अन्य व्यापारी की तरह नहीं बेचा गया था, और, इस तरह, विद्वान एकल न्यायाधीश ने गलती थी, सीमित सीमा तक, उन्होंने याचिकाकर्ता को अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत को लागू करते हुए धनवापसी के लाभ से इनकार कर दिया था। विद्वान वकील भद्राचलम पेपरबोर्ड्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य पर भरोसा करेंगे (51), मेसर्स वाम ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड बनाम यू0 पी0 का राज्य और अन्य (52), मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (53), और एएसएसटी। कॉम., आयकर, राजकोट बनाम सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (54)।

57. दूसरी ओर श्री मोहित मौलेखी, विद्वान संक्षिप्त धारक, आगे प्रस्तुत करेंगे कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ता को धनवापसी से इनकार कर दिया था क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा खैर लकड़ी को वैसे ही बेचे जाने की संभावना थी, और इसका उपयोग किसी अन्य उत्पाद के निर्माण के लिए नहीं किया जा रहा थाय और विक्रेता का पता चालान में परिलक्षित होता है क्योंकि उन्होंने नीलामी में भाग लिया था, बोली उनके पक्ष में डाली गई थी, बिक्री पूरी हो गई थी, और बिक्री चालान में उनका नाम और पता प्रदर्शित होना आवश्यक है।

58. कानून के अधिकार के बिना कर का संग्रह और/या प्रतिधारण, उस व्यक्ति को, जिससे यह एकत्र किया जाता है, अपने धनवापसी का दावा करने का अधिकार देता है। यह भी कहा जा सकता है कि राज्य पर धन वापसी का एक संबंधित दायित्व भी इससे आता है। इसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत और उनके आधार पर उत्पन्न धनवापसी का अधिकार कहा जा सकता है। अनुच्छेद 265। लेकिन, इससे ऐसा नहीं होता है कि धनवापसी स्वचालित रूप से होती है। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 53, अनुच्छेद 265 को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। इसे प्रस्तावना में परिकल्पित आर्थिक और सामाजिक न्यायाधीश की अवधारणाओं और अनुच्छेद 38 और 39 में उल्लिखित राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। क्या धन वापसी का अधिकार कानून के कानून के एक असंवैधानिक प्रावधान के तहत भुगतान किए गए करों को अनुच्छेद 265 से प्रवाहित एक संवैधानिक अधिकार के रूप में माना जाता है या अनुबंध अधिनियम की खंड 72 द्वारा प्रमाणित किए गए वैधानिक अधिकार/न्यायसंगत अधिकार के रूप में माना जाता है, परिणाम समान है—धनवापसी का कोई स्वचालित या बिना शर्त अधिकार नहीं है। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 53,

59. भद्राचलम पेपरबोर्ड्स लिमिटेड. 51 में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ताओं ने वन विभाग की कर देनदारी की प्रतिपूर्ति की थी, अपीलकर्ताओं ने कागज बोर्डों आदि के निर्माण के लिए माल का उपभोग किया था, इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा उपभोक्ता को कर देनदारी देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ था, और इसके नतीजन, अपीलार्थी उनसे एकत्र किए गए कर की वापसी के हकदार थे, पूरी अवधि के लिए नहीं, बल्कि रिट याचिका भरने की तारीख से तीन साल पहले की अवधि के लिए।

60. भद्राचलम पेपरबोर्ड्स लिमिटेड. 51 के बाद, उच्चतम न्यायालय ने मेसर्स वाम ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड. 52 में यह अभिनिर्धारित किया कि पूरा विवाद यह था कि क्या जो बेचा गया वह मूल वस्तु नहीं है, बल्कि कुछ अन्य वस्तुएं हैं जो मूल वस्तुओं से निर्मित की गई थीं, फिर क्या अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू होता है, दूसरे शब्दों में, क्या अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत को

उस मामले तक बढ़ाया जा सकता है जहां जो बेचा जाता है वह मूल वस्तु नहीं है, बल्कि मूल वस्तुओं से निर्मित कुछ अन्य वस्तुएं हैं, भद्राचलम पेपरबोर्ड्स लिमिटेड. 51 में, मूल वस्तु बांस और दृढ़ लकड़ी थी, जिसका उपयोग कागज बोर्ड बनाने के लिए अपीलकर्ता द्वारा किया गया था उस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इस पर कोई सवाल नहीं था ।

61. इसलिए, हम श्री के अधीनता में काफी बल पाते हैं। एस0 के0 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता पोस्ती ने कहा कि अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत का मौजूदा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई अनुप्रयोग नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी गई खैर लकड़ी को वैसा नहीं बेचा गया था जैसा वे थे, बल्कि निर्माण के लिए इनपुट के रूप में उपयोग किया गया था।

62. हालाँकि, यह प्रश्न विद्या सम्बन्धी है क्योंकि उत्तराखंड बिक्री कर कानूनों के तहत याचिकाकर्ता द्वारा पहले भुगतान किए गए कर के अवशिष्ट की वापसी का प्रश्न केवल तभी उत्पन्न होगा जब निगम द्वारा याचिकाकर्ता को खैरवुड की बिक्री को सीएसटी अधिनियम की खंड 3 (ए) के दायरे में आने वाली अंतर-राज्यीय बिक्री माना जाए। चूंकि हमने अन्यथा राय दी है, और यह माना है कि विषय बिक्री उत्तराखंड बिक्री कर कानूनों के तहत कर के लिए उत्तरदायी एक अंतर-राज्य बिक्री है, न कि सीएसटी अधिनियम के तहत, निगम द्वारा एकत्र किए गए कर के अवशिष्ट की वापसी का सवाल याचिकाकर्ता से उत्पन्न नहीं होता है।

#### VIII- निर्णय:

63. इसके परिणामस्वरूप, विशेष अपील सं. उत्तराखंड राज्य द्वारा 2013 का 249 मंजूर किया गया है, और विशेष अपील सं. निर्धारिती-विक्रेता द्वारा प्रस्तुत 2013 का 52 खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि, परिस्थितियों में, बिना किसी लागत के।

(आलोक सिंह, जे.) (रमेश रंगनाथन, सी0 जे0)

18.12.2018 18.12.2018

जी.